Appointment of Medical Officers in CGHS (Homoeopathy)

1194. SHR1 GHUFRAN AZAM: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether Government had conducted interview for the appointment of Medical Officers in Homoepathic stream under CGHS in the month of February this year;.

(b) if so, the names of Medical Officers selected for appointment in Homoeopathy under CGHS;

(c) whether the said Medical Officers have since been given appointment letters;

(d) if so. since when, and if not. the reasons therefor;

(c) whether keeping in view the steep shortage of Medical Officers in Homoeopathy in CGHS. Government propose to appoint them immediately and also take action against those who arc deliberately trying to delay the issue: and

(0 if «>. the details thereof?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI SALEEM IQBAL SHERVANI): (a) and (b) The Union Public Service Commission held the interviews for selecting candidates to the posts of Medical Officer (Homoeopathy) between 19th to 28th Feb.. 1996 and recommended the following candidates for appointment to the post in question;

(i) Dr. P. Kameshwar Rao
(ii) Dr. Ashish Kumar Mandal
(iii) Dr. Abhijit Chattopadhyay
(iv) Dr. Sangeeta A. Duggal
(v) Dr. Pran Ranjan Haider
(iv) Dr. Madan Mohan R.

(c) and (d) After completing the administrative formalities, offer of appointment to the recommended candidates have since been made in October, 1996.

(c) and (f) These officers will be allowed to join the post of Medical Officer (Homoeopathy) on receipt of their letter of acceptance and on completion of verification of their eharracter and antecedents and medical examination.

जीवन बीमा निगम के राजकोट मंडल में अधिकारियों/कर्मचारियों की स्थानान्तरण नीति

1195. **श्री चिमनभाई हरिभाई शुक्ल:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय जीवन बीमा निगम के राजकोट मंडल में अधिकारियों/कर्मचारियों की स्थानान्तरण नीति क्या है;

(ख) क्या सरकार को राजकोट में जीवन बीमा निगम में अधिकारियों/कर्मचारियों के काफी समय तक रहने की जानकारी है;

(ग) क्या उन्हें गुजरात से अन्य राज्यों में स्थानांतरित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है;

(ङ) यदि नहीं, तो उनको राजकोट में लम्बे समय तक रखने के क्या कारण है; और

(च) सरकार ने लम्बे समय से वहां काम करने वाले कर्मचारियों को स्थानान्तरण करने के लिए क्या कदम उठाये है?

वित्त मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम): (क) भारतीय जीवन बीमा निगम ने सूचित किया है कि स्थानान्तरण नीति, जो राजकोट मंडल सहित सभी मंडलों के लिए एक समान है, में कर्मचारियों के विभिन्न वर्गों के लिए विभिन्न मानदंड है। इसकी स्थानान्तरण नीति की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है:—

(i) सामान्यतः श्रेणी III और IV के कर्मचारियों का स्थानान्तरण शाखाओं की आवश्यकता, कर्मचारियों के व्यक्तिगत अनुरोधों और प्रोन्नति पर आधारित होता है।

(ii) विकास अधिकारी के रूप में ज्ञात श्रेणी II के कर्मचारी सामान्यतः स्थानान्तरित नहीं किए जाते है।

(iii) प्रशासनिक अधिकारी के स्तर तक के श्रेणी -I के अधिकारियों का स्थानान्तरण एक ही मंडल के

अन्तर्गत अथवा समीपवर्ती मंडलों में किया जाता है। तथापि, उन युवा अधिकारियों को, जिनके संगठन में उच्च पदों पर जाने की संभावना होती है, आवधिक स्थानान्तरणों के माध्यम से विभिन्न स्थानों पर कार्य करने का अनुभव प्राप्त करने के अवसर दिए जाते हैं। सहायक मंडल प्रबंधक, मंडल प्रबंधक और वरिष्ठ मंडल प्रबंधक के स्तर के अधिकारियों का स्थानान्तरण मुख्यतः निगम की आवश्यकताओं, अधिकारियों की आयु और उनकी व्यक्तिगत परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है।

(ख) से (च) जीवन बीमा निगम ने सूचित किया है कि राजकोट में तैनात श्रेणी-I के सभी पांचों अधिकारी वहां पिछले 10 वर्ष से भी अधिक समय से कार्यरत हैं। तथापि, जीवन बीमा निगम ने यह भी सूचित किया है इनमें से एक अधिकारी एक वर्ष के अन्दर ही सेवानिवृत्त होने जा रहा है, दूसरा अधिकारी दो वर्ष से भी कम समय में सेवानिवृत्त हो जाएगा और अन्य दो अधिकारी तीन वर्ष से भी कम समय में सेवानिवृत्त हो जाएंगे। तकनीकी विभाग में कार्यरत केवल एक अधिकारी कुछ वर्षों के पश्चात् ही सेवानिवृत्त होगा। उसे वहां पर संगठन के हित में अनुभवी व्यक्तियों की कमी के कारण रखा गया है।

जीवन बीमा निगम में अधिकारियों का स्थानान्तरण एक आन्तरिक प्रशासनिक विषय है जिसका सरकार से कोई संबंध नहीं है।

Comprehensive proposal for Modernisation and Expansion of the Department of Radiotherapy in Safdarjung Hospital

1196. SHRI NILOTPAL BASU: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether Government have received a comprehensive proposal for modernisation and expansion of the Department of Radiotherapy in Safdarjung Hospital, New Delhi from the Dncology Department for taking it up in the 9th Five Year Plan;

(b) if so, the details thereof

(c) whether Government have taken decision on the proposal in view of the urgent need for fight against cancer; and

(d) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI SALEEM IQBAL SHERVANI): (a) and (b) The hospital authorities have proposed procucement of euqipments like linear accelerator, 3 Treatment Planning System, Computerised Compensator Making Device etc., creation of post of Specialists (Radiotherapy) and other supporting staff. A Pallistive Care Unit is also a part of the Plan.

(c) and (d) No Sir. The proposal has to be considered as a part of the Ninth Plan 1997-2002 within the overall priorities and allocation of resources to the hospital.

Instruction to Regional Rural Banks Regarding House Building Loan

1197. SHRI E. BALANANDAN: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether Government have issued instructions to the Regional Rural Banks to extend house Building Loan for the construction of houses only within the respective States;

(b) what is the rule prevailing in the banking sector in this regard; and

(c) whether non-tribal employees of the rural banks in Meghalaya can construct their houses within the State, if not what action has been taken by Government for them?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI P. CHIDAMBARAM): (a) Presumably the Hon'ble Member is referring to House Building Loans to the employees of Regional Rural Banks (RRBs). RRBs were allowed to extend house building loan to the employees for construction of a house within their area of operation. However, having regard to the limited area of operation National Bank for Agriculture & Rural Development (NABARD) have